

सम्पादकीय

खत्म होता कानून का खौफ

लोग कानून का सम्मान करें स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना बहुत जरूरी है। कानून का खोफ खस्त हो गया तो समाज पूरी तरह से अराहत के जाएगा। ऐसा लगता है कि पुलिस, कानून और अदालतों का योगी अब खत्म होता जा रहा है। कानून तोड़ा हैंसियर का सचाल बनता जा रहा है। आज समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। लोगों जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षा देना सबसे जरूरी काम है। महानगरों में देश हो या दूर होइ खोफजदा है। राह चलते ही और गलत इश्वरिंग से कोई किसी को कुचल कर भाग जाए, कोई नहीं जानता। हिंट एंड रन के मामलों में लगातार बढ़तीरी हो रही है लेकिन ऐसे मामलों में मरने वाले लोगों को कभी न्याय नहीं मिलता। कानून के शासन का अर्थ समाजी करने वाली ताकतों को रोकना और कमज़ोर को इंसाफ देने वालों को देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे इंडिया की कोई कीमत ही नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में देर रात बेखौफ दो युवकों द्वारा कानून-व्यवस्था की धर्जियां उड़ाते हुए दिल्ली पुलिस के सिपाही संदीप को सुने कुचलकर मार डाना गया। इससे स्पष्ट है कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं था।

प्रथम दृष्टि में तो यह माला हिंट एंड रन का ही लगता था लेकिन जांच के बाद नया एंपॉल सामने आने पर यह सीधे-सीधे हया का समाज बनता है। कांटेबल संदीप ने लापत्ती के साथ चला रहे लोगे थे। यद्यपि पुलिस के सिपाही संदीप को रोके की कोशिकी की तो उन्होंने केवल संदीप की ओर भाइ को रोका को टक्का मारी बल्कि उसे 10 मीटर तक घसीटा भी गया। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि कांटेबल संदीप ने दो लोगों आरोपियों को दो बार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के अरोप में हवालत भेजा था जिससे वे सिपाही से रिंजन रखने लगे थे। यद्यपि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिससे पुरा घटनाक्रम परत-दर-परत खुल गया है। आम धारणा यह बन चुकी है कि जब इस देश में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आप लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। ऐसी घटनाएं दिल्ली में ही नहीं बल्कि हर राज में हो रही हैं। कहीं शाखा मार्फियत, कहीं अधिक खनन मार्फियत, कहीं कोल मार्फियत तो कहीं आपाधिक तत्व बेखौफ होकर कांटेबल अफसरों और कर्मचारियों को कुचलते रहे हैं। पुलिस तंड बड़े से बड़े एक्शन के दावे तो करता है लेकिन परिणाम ढाके के तीन पात ही निकलते हैं। जब जलों में बंद गैंगस्टर मर्डिका को बिना किसी खोफ के नियमों को उड़ाने कर दूरव्यू देने लगे, जेल में बैठकर अपहरण, धमकी देकर फिरोती वसूलने का धंधा चलाने लगे तो फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था की रिप्टिंग कीसी है। मुझमई और दिल्ली में अभिनन्दन खान सहित कई प्रतिष्ठित व्यापारियों के घरों के बाहर फायरिंग कर आंकड़ पैदा करने और फिरोती मांगने की घटनाओं में लगातार वृद्ध हो रही है। दिल्ली में एक ही दिन में महानी कारों के सैकड़ हैं शैशव, एक हाँड़ और एक मिट्टी की डुकान को निराकार गोलीबारी की घटना सामने आई है। यह घटनाएं गिरोहों द्वारा जबरन वसूली से जुड़ी हुई हैं। पंजाब में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वहां तो विदेश में बंदे गैंगस्टर पंजाब में सक्रिय गैंगस्टरों की मदद से लगातार हत्याएं कर रहे हैं।

शहिद्यत

बढ़ता राजस्थान

'वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार

गए इस आसमान से'

नमस्कार साथियों हमारे आज की संक्षेप कलम के स्टार हैं राजस्थान पुलिस की शान दिखी एसपी राजवीर गहरा। एसपूर्ण शिक्षा वहां से प्राप्त की पिंडियां आर एन कर्फ्या राजसीय महाराजा रामानंद शेखावाटी में प्रेसिपर रहे। बीड़ी की ओर 1986 में सब इंस्पेक्टर के पाप पर भर्ती हुए तथा वर्ष 2010-11 में इंस्पेक्टर बने तथा वर्ष 2021-22 में डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोट हुए। वर्तमान पद थायान की डिप्टी एसपी प्रश्नावाट उड़ायुर। इससे पहले को खंडर सिरोही में रहे, सब इंस्पेक्टर जिला छूलू में हमारी का बास, सिद्धपुर राजगढ़

ड्रैफ्टिक चूरू और रतननगर रहे। दुधवा खारा संकर जिले में श्रीधरपुर, हुनुमानगढ़ जिले में हुनुमान जंक्शन अलवर में गोविंदपुर और लक्ष्मणगढ़ रहे। इंस्पेक्टर पद पर आपे के बाद सरकार ने इहें चुरू जिले में सररामशहर, संकर में फोहपुर कोतवाली, महिला थाना, मानव संकरी नियंत्री दिल्ली, नियंत्री यूनिट, नीम का थाना और कोतवाली लगाया। जयपुर कमिश्नरेट में ये जवाहर नगर रहे। अलवर में राजगढ़ और चिंचावी रहे। डिप्टी एसपी पर पांच वर्षों के बालियन दिल्ली, सीओओ रेवरेंट सिरोही और हाँड़ बंदूक वेदवेद उदयपुर वर्तमान में स्थापित है। राजस्थान पुलिस के जांबाज पुलिस अधिकारी के रूप में राजवीर गहरा की गिनती होती है इहोंने अपनी बेल पुलिसिंग और खाकों के प्रति अपने जांबाज जन्में के रूप में दिखाये हुए बड़े-बड़े अपराधियों को उनके सही उड़ान दिल्लैंडे किनारे पर दिखाया। ये जहां भी रहे



राजीव रात्होर (डिप्टी एसपी, राजसमान पुलिस)

वहां के पुलिसबल ने इनका इस्तकबाल किया और हौसला अपाई भी की ओर अधिकारियों से मिले हुए प्रेस और सेहे के कारण इहोंने अपराधियों और अपराध पर अंकुरा लगाए। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इस जांबाज ऑफिसर को सल्ट करती है और उनके उड़ान के रूप में दिखाये हुए बड़े-बड़े अपराधियों को उनके सही उड़ान दिल्लैंडे किनारे पर दिखाया। जय हिंद रुपक शर्मा

आज का इतिहास

2 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

- ब्रिटेन के किंग हेनरी सप्तम ने 1492 में फ्रांस पर आक्रमण किया।
- 1924 में राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया गया जेनेवा प्रस्ताव।
- महस्ता द्वारा 1924 में स्वीकृत हुआ किंतु बाद में उसकी पुष्टि नहीं हुई।
- श्यामा प्रसाद मुख्योंने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की।
- सामुद्रिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई।
- बम्बू (अब मुंबई) में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1961 में हुआ।
- तकलीन राष्ट्रपति वी.वी.पिंग ने 1971 में गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिंदता हाऊस देश को समर्पित किया।
- तेहरान में 1982 को हुए बम विस्फोट से 60 मरे, 700 घायल।
- दहें नियेधाजा संशोधन अधिनियम 1985 को अस्वित्त में आया।
- दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 1988 को 24वें ओलंपिक खेलों का समाप्त।
- तमिलनाडु में मंडपम और पम्बन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल 1988 में खुला।
- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2000 में भारत की चार दिवसीय ब्लादिमीर पुतिन 2000 में भारत के देश के संसद विलायतों में 2001 में अक्टूबरान्सन पर हमले के लिए ही दी गई।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने कानून को अपनी में 5900 सैनिक भेजने का प्रस्ताव 2004 में मंजूर किया।

2 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

- बिहार के प्रमुख गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी प्रजापति मिश्र का जन्म 1898 में हुआ।
- भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ।
- प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा का जन्म 1924 में हुआ।
- हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक शंकर शेष का जन्म 1933 में हुआ।
- प्रसिद्ध फिल्म अधिनेत्री आशा पारेख का जन्म 1942 में हुआ।
- भारतीय महिला हाँकी टीम की पूर्व कसान प्रीतम सिवाच का जन्म 1974 में हुआ।
- प्रवित्री उद्दास का जन्म 1976 में हुआ।
- 'अशोक चक्र' से सम्मानित भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हांगन दादा का जन्म 1979 में हुआ।
- मारियोन बार्टली का जन्म 1984 में हुआ।

2 अक्टूबर को हुए निधन

- विख्यात चिकित्सक राजा रवि वर्मा का निधन 1906 में हुआ।
- भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत का निधन 1964 में हुआ।

एक जवाबदेह चुनावी घोषणा पत्र की दरकार

नरेश कौशल

दे श में आम चुनावों के बाद हो रहे

विधानसभा चुनावों में एक बार फिर मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का खेल जॉर-शोर से चल रहा है। जनता में राजनीतिक दलों की घटती साथ और रीति-नीतियों के प्रति जनता में उपजे अविश्वास के बीच राजनेता मुफ्त का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वे लोकतुंभावन का शर्टफ़िक्ट रास्ता अखिलयार कर रहे हैं। वे मुफ्त का चंदन धिस मेरे नंदन की कहावत को अपना रहे हैं। उन्हें पता है कि मुफ्त के माल का पैसा कौन-सा उनकी जेब से जा रहा है। बोझ तो सरकारी खजाने पर पड़ेगा। दुर्भाग्य से देश में ऐसी कोई नियामक व्यवस्था नहीं बन पायी कि मुफ्त की रेवड़ियों के खर्च की जबाबदेही नेताओं व राजनीतिक दलों के लिये तय की जा सके। चुनाव आयोग भी इस धातक रिवाज पर रोक लगाने में विफल ही लगता है। हकीकित यह है कि जब तक हम जनता को जागरूक नहीं करेंगे और जनता ही नेताओं पर दबाव नहीं बनाएंगी, तब तक मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का यह खेल यूँ ही चलता रहेगा। वैसे हकीकित यह है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, राजनीतिक दलों के मुफ्त के बादों के घोषणापत्रों पर लगाम नहीं लगेगी। यह एक हकीकित है कि सरकारें व राजनीतिक दलों के तमाम थोथे दावों के बावजूद हम देश के अधिसंख्य नागरिकों को राजनीतिक रूप से इतना सजग-सचेत नहीं कर पाए हैं कि वे मुफ्त के प्रलोभनों, जाति, धर्म व क्षेत्रीयता की संकीर्णताओं से उठकर मतदान कर सकें। यदि देश का अधिसंख्य मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक होता तो मुफ्त की रेवड़ियों को वह टुकरा देता।



कितना लोकतांत्रिक अधिकारों के नीति सजग स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सर्वप्रथम किसी भी राज्य या देश के मौजूदा बजट का आकलन करना होगा। यह कि राज्य को किन-किन स्रोतों से उपजस्त्व प्राप्त हो रहा है। कितना रुपण राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया गया है। राज्य और कुल ऋण का कितना बोझ है। उस पर कितना व्याज लगातार राज्य को देना पड़ रहा है। यह सब राजनीतिक दलों व लोकतांत्रिक अधिकारों को जनता को बताना चाहिए। मतदाताओं को अहसास करना होगा कि उसके पास केतनी चादर है और उसे कितने लोक और पसारने होंगे। एक बात तो बताय है कि देश-प्रदेश के भार्थिक स्वास्थ्य के हित में हर लोकलुभावन घोषणाओं और मुफ्त की रेवड़ियों का प्रचलन होगा। मतदाताओं में राष्ट्रीय और प्रदेशी लोकलुभावना जाग्रत करनी होगी। वहीं दूसरी ओर राशन बांटकर जनता को सकारात्मक जनाये रखने की नीति बदलनी होगी। लोगों द्वारा विसरखी देने के बजाय उन्हें अपने देने लायक बनाया जाए। उन्हें मुफ्त वजाय सस्ता लोन दिया जा सकता है। अभ्यना काम धूंधा शुरू करके आत्मीयता वाले हैं लोकलुभावन स्थायी होगा और द

कि यदि ऋण लेने से वे कोई काम-धंधा चला सकें तो दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। सरकार व राजनीतिक दलों को सरकारी कर्मचारियों व वेतनभागियों को बजट की वास्तविक स्थिति से भी अवगत कराना होगा। होता यह है कि राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति को जानने हुए भी कर्मचारी संगठन सुविधाओं को बढ़ाने के लिये आंदोलन करते रहते हैं। उन्हीं से राय लेनी होगी कि यदि उनके वेतन-भत्ते बढ़ाने हैं तो बजट में उस राशि की पूर्ति आय के किन स्रोतों से की जा सकती है। एक बात तो तय है कि निश्चित रूप से

फ्री बिजली और पानी की नीति बंद करनी होगी। हां, शुद्ध पेयजल व शुद्ध पर्यावरण निःशुल्क पाना नागरिकों का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर बजट में शिक्षा, जन स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का कल्याण, महिलाओं के उत्थान हेतु पौष्टिक आहार जुटाने तथा समाज व बाल कल्याण हेतु अधिकतम प्रावधान होना चाहिए। दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों, खेलकूद संस्थानों आदि के लिये प्राथमिक आधार पर बजट की दरकार रहेगी। शिक्षा के स्वरूप में एकरूपता होनी चाहिए। होना तो यह

चाहिए कि सरकारी स्कूलों के शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर, नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो हो। आम आदमी सरकार ने दिल्ली में जिस शिक्षा नीति को लागू किया, उसके अच्छे परिणाम मिले हैं। इसी तरह मोहल्ला क्लीनिक के प्रयोग को भी सराहा गया है। एक आदर्श घोषणा पत्र में ऐसी सुविधाओं का प्रावधान तो होना ही चाहिए। वहीं बोट जूटों के लिये अवैध बस्तियों को वैध बनाने का जो दुर्भार्थपूर्ण खेल शुरू हुआ है, उसका घातक असर नागरिक सेवाओं पर पड़ रहा है। जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की कमाई से कानूनी रूप से वैध मकान बनाए हैं और उसकी बड़ी कीमत चुकाई है, उन्हीं को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। अवैध रूप से बसायी गई इन बस्तियों के लिये बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं देने का नकारात्मक प्रभाव वैध बस्तियों के नागरिकों पर पड़ रहा है। जरूरतमंद नागरिकों हेतु छत या बस्ती बसाने के लिए योजनाबद्ध नीतियां बनायी जानी चाहिए। उधर, बजट में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। विभिन्न गोष्टियों में लोगों की बजट के बारे में राय लेनी होगी कि राज्य की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर रखेते हुए कैसा बजट बनाया जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से बचना होगा। ताकि करदाताओं पर करों का अतिरिक्त बोझ न पड़े। आखिरकार इस प्री राशन का बोझ देश की मध्यवर्गीय जनता की जेब पर ही पड़ता है। जिसकी बजह से मध्यवर्ग पिसता है- अमीर और गरीब के पाट के बीच में। सही अर्थों में होना तो यह चाहिए कि राज्य की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने को कदम उठाये जाएं। राज्य सरकार पर जो करोड़ों रुपये का ऋण का बोझ है, उसे उत्तराने के उपाय घोषणा पत्र में दर्ज हों कि कर चुकाने के लिये सभी किस तरह से सहयोग करें। जैसे कि पहले कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिये ज्यादा बजट का प्रावधान होना चाहिए। दवाइयां सस्ती करने के लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों के लिये खाद, बीज, कीटनाशक व सिर्चाई की सुविधा तथा खेती में काम आने वाले उपकरण मसलन ट्रैक्टर आदि सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराये जाएं। बजाय कि ऋण माफ करने तथा सस्ती बिजली-पानी देने के। यदि हम किसान की कृषि उत्पादन की लागत कम कर देंगे, तो फिर किसान की सरकार पर निर्भरता कम हो जायेगी। सत्ताधीशों को याद रखना चाहिए कि सरकार का पहला फर्ज लोककल्याणकारी शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। बच्चों के लिये सस्ती एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सत्तर वर्ष से ऊपर के लोग सरकार की प्राथमिकता में हों। उनके लिये निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हो। साथ ही बदलते सामाजिक दौर में असहाय स्थिति में रह रहे बुजुर्गों के लिये गुणवत्ता वाले निःशुल्क वृद्धाश्रमों की व्यवस्था भी बढ़े पैमाने पर की जाए। इसके बावजूद यदि राजनीतिक दलों व नेताओं को कुछ मुफ्त बांटने की ज्यादा ही इच्छा हो तो वे अपने या पार्टी फंड से ऐसी व्यवस्था करें। साथ ही पार्टी फंड से जनकल्याण के बजट में योगदान करें। चुनाव के दौरान प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अरबों रुपये जैसे पानी की तरह बहाये जाते हैं, यदि उसी धन को कमज़ोर वर्गों के कल्याण व नागरिक सुविधाएं सुधारने के लिये लगाया जाए तो जनता का ज्यादा भला होगा। अब वक्त आ गया है कि देश की जनता, जागरूक स्वयंसेवी संस्थाएं तथा राजनीतिक दल इस समस्या का सार्थक समाधान निकालें।

बेकाबू हो सकता है युद्ध

लेबनान में शुक्रवार को हुए इस्साइली हमले में हसन नसरल्लाह का मारा जाना हिज्बुल्ला के लिए ऐसा झटका है, जिससे उबरना उसके लिए आसान नहीं होगा। इस्साइली सेना और नेतन्याहू सूरक्षार के लिए यह उतनी ही बड़ी कामयाबी है। अफसोस की बात यह है कि इस कथित झटके या कामयाबी के बाद भी इस क्षेत्र में शांति की संभावना मजबूत नहीं हुई है। इसके उलट संघर्ष के बेकाबू होने का खतरा बढ़ गया है। पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से हिज्बुल्ला का नेतृत्व कर रहा नसरल्लाह मध्यपूर्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार किया जाता था। उसकी कमी की जल्द भरपाई होना मुश्किल है। मगर हिज्बुल्ला के लिए यह इकलौता झटका नहीं है। हाल के हमलों में उसके एक दर्जन से ज्यादा टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं। बहुचर्चित पेजर और वांकी टॉकी हमलों ने उसके इंटरवल काम्युनिकेशन सिस्टम को भी लगभग खत्म कर दिया है। ऐसे में खुद को समेटकर इस्साइल पर दोबारा वैसा ही हमला करना हिज्बुल्ला के लिए काफी मुश्किल होगा। ताजा झटका कितना भी बड़ा हो, यह समझना गलत होगा कि इससे हिज्बुल्ला इस्साइल के सामने समर्पण कर देगा। पिछले कुछ दशकों में हिज्बुल्ला दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर बन चुका है। उसके पास 1,50,000 से अधिक रॉकेट और मिसाइलों बताई जाती हैं। उसकी सैन्य ताकत किसी मिडल साइज के देश के बराबर मानी जाती है। हिज्बुल्ला ने कहा भी है कि वह इस्साइल के खिलाफ अपना अधियान जारी रखेगा। कुछ समय पहले तक 12 देशों की ओर से प्रस्तावित युद्धविराम को लेकर जो भी बच्ची-युची उम्मीद थी, वह अब समाप्त हो गई है। ताजा कामयाबी ने इस्साइल का उत्साह और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिज्बुल्ला की मिसाइलों का खतरा समाप्त करने के बाद इस्साइल अपने सैनिकों को लेबनान में घुसने का आदेश देता है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक और लंबी लड़ाई की शुरूआत साबित हो सकती है। निगाहें ईरान पर भी टिकी हैं। वह पहले से नाराज है। तेहरान के एक गेस्टहाउस में हमास नेता इस्माइल हानिये की मौत का बदला भी उसे लेना है। नसरल्लाह की मौत उसके लिए भी झटका है। देखने वाली बात यह है कि उसकी प्रतिक्रिया कितनी और कैसी होती है। जहां तक भारत की बात है तो बाकी पूरी दुनिया की तरह वह भी यही चाहेगा कि संघर्ष की यह आग ज्यादा न फैले। इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोर जैसे दूरगामी हितों को फिलहाल छोड़ दें तो भी युद्ध का बेकाबू होना भारत को ही नहीं, ग्लोबल इकॉनॉमी को भी चुनौतियों के भंवर में डाल सकता है।

४ सुरेश सेठ

31 मेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए एक नया संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि वह आने वाले दिनों में भारत को पुष्टि बनाएंगे और पुण्य की पौर्तीयों से इसे विकसित करेंगे। उन्होंने पी से प्रगतिशील भारत का उत्त्लेख किया, जिसका अर्थ है हमारे संविधान की प्रतिबद्धता कि हम देश में प्रजतांत्रिक समाजवाद स्थापित करेंगे। यह वर्चितों के लिए आशा की किरण है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ गई है। यू से अजेय भारत का संकेत है कि भारत की सेना आत्मनिर्भर और आधुनिक हो गई है। देश की अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस से आध्यात्मिक भारत का अर्थ है कि आधुनिकता की रौ की बजाय आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना भारत का लक्ष्य होगा। अध्यात्म का सही संदेश अगर कोई दे सकता है तो वह भारत है, लेकिन यह संदेश कहरता से मुक्त होना चाहिए। एच से मानवता का समर्थन करता भारत और पी से समृद्ध भारत का संकेत, मंदी के अंधड़ में फंसी दुनिया में भारत की तेज विकास दर को बनाए रखने और अपनी मंडियों में निवेश की मांग को कम न होने देने की ओर है। इन सभी पहलुओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत को प्रगतिशील, अजेय, आध्यात्मिक और समृद्ध बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत ने अपनी आजादी के शतकीय महोत्सव में विकसित भारत की स्थापना का लक्ष्य रखा है, और उसका आदर्श है कि वह आर्थिक महाशक्ति बनेगा। न्यूरॉक में प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक नमस्ते को वैशिक पहचान बनाने का समय आ गया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के



प्रकारात्मक मूल्यों को अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था में प्रमुखता देने का सदेश दिया। मोदी ने प्रवासी भारतीयों को देश का ब्रांड एक्सेसडर बताया और कहा कि भारत आज अवसरों की धरती है। भारत में नेतृत्व करने की क्षमता है और वह रुकने या थमने वाला नहीं है। यह विचारणा वास्तव में उत्साहजनक है। मोदी यहां अपने देश में ही रहे सेमीकंडक्टर सेक्टर के तेज विकास की ओर दृश्यांक कर रहे थे, जो भारत के डिजिटल परिवर्तन का हस्ता है। उन्होंने मेड इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर चिप्स को विकसित भारत की उड़ान के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि, इस डिजिटल युग का लाभ देश की गरीब रोजगारी है। मोदी वर्गों डिजिटल मोदी के लक्ष्यों उत्सज्ज भारत प्रट्टीव्हण

और वचित आबादी तक पहुंचाना जरूरी है, जो और और महंगाई की समस्याओं का सामना कर रही बढ़ादी का नेतृत्व सशक्त है, लेकिन उन्हें इन वचित की जरूरतों का ध्यान रखना होगा, ताकि वे इल भारत में शिक्षा और अवसरों से वचित न रहें। जी ने प्रवासी भारतीयों के सामने यह दावा किया कि भारत पहला जी-20 देश है जिसने पेरिस जलवायु को हासिल किया है, और उनका कार्बन दुनिया के मुकाबले कम है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति की राह पर अग्रसर है और पर्यावरण के संकट का सामना करने के लिए अग्रणी

भूमिका निभाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ-साथ विकसित पश्चिमी देश भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं, जिसके पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग सभी के लिए एक गंभीर सकट है। पिछले दिनों मौसम के असाधारण परिवर्तनों ने न केवल भारत को, बल्कि पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। इसके परिणामस्वरूप कृषि, उत्पादन और निवेश में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे मांग में कमी आई है। अमेरिका ने इस समस्या से निपटने के लिए अपनी फेडरल दरों में 50 बेसिस प्लाइंट की कमी की है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र इस संकट का सामना कर रहा है, जिससे मंदी और निवेश की अनिश्चितता उत्पादन की गणनाओं को अस्तव्यस्त कर रही है। इसलिए, दुनिया को समावेशी विकास का नया रास्ता अपनाना होगा। भारत, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, अगर बदलाव का नेतृत्व करता है, तो यह सकारात्मक कदम होगा। पश्चिमी और संपन्न देशों को तीसरी दुनिया के देशों की शक्ति का अहसास करना होगा और भारत की नई ताकत को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि सभी मिलकर मौजूदा चुनौतियों पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया में भुखमरी, महांगाई और बेरोजगारी का संकट समाप्त हो सकता है, जो अब केवल तीसरी दुनिया के देशों में नहीं, बल्कि संपन्न देशों में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा, लोकतंत्र ही इस दुनिया में मुक्ति और विकास का सही रास्ता है। अधिनायकवादी महत्वाकांक्षाएं संघर्ष और तनाव पैदा करती हैं, जैसा कि पिछले दो-तीन वर्षों में देखा गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्लाम-हमास संघर्ष के चलते दुनिया में शांति का माहौल नहीं बन रहा है, और यदि यह स्थिति बढ़ती है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

आप सिर्फ एक संख्या हैं

४ शैलेश श्रीवास्तव

ये वाला यूट्यूब चैनल देखा है ही गंदा है यार, पता नहीं क्या है, गालियां देता रहता है, और लोग हैं इसे। एक दोस्त ने कहा। आपको बैठे देखते हो? मैंने कहा। हाँ मैं तो सारे दृष्टि हूं, तभी तो पता चला। उसके बाद मैंने की अगलों तो को ऐसे कंटेंट प्रसंदर्शन करने वाला बनाया क्यों जाता है। क्या लगता है इंसान हैं। हाँड़ मास्क के बने हुए, चलाक्या, अहसास, गुस्सा, स्नेह, गतिनियन्त्रण, हमने कभी बचपन में किताबों में शरीर में दिमाग भी है। यहां कुछ लगता नहीं है वो आपको सिर्फ एक मानते हैं। सोशल मीडिया के जरूरत में अपनी बातें पहुंचाना आसान हो गया चला की हमारे आस-पास बहुत से हैं जो अपनी कल्पना से बहुत ही रुक्ष अलग तरह का कंटेंट बनाते हैं उनमें कितने मायने रखते हैं, एक व्यू या बढ़ने पर कितनी खुशी मिलती है। से परे उसी कंटेंट से दूसरी तरफ दिल दिमाग पर कितना असर हुआ, या खराब, वो नरम दिल बना या संवेदनाएं जगी या वहशीणन या हंसी हमने किसी के धर्म, जाति या लिंग पात्र बना दिया। हम अबसर कहतें हैं मैं अच्छी मूलीज नहीं बनती क्योंकि माझे जैसी मूलीज सिनेमा में देखेने वाले हैं देखने क्या कूल है हम या



एक त्योहार की तरह देखा जाता है। सरकारी भाषा में लोकतंत्र का त्योहार और बहुत सी जनता की भाषा में नेताओं से पैसा लूटने का त्योहार। 500 रुपये, दारू, कंबल, पंखा, साड़ी ये सब तो आपने सुना ही होगा कि नेता बाट रहे हैं, दरअसल ये जनता में कुछ ठेकेदार होते हैं उनकी डिमांड होती है। अब ये पैसा, दारू, कंबल या बाकी चीजें सबको तो मिलती नहीं हैं, कुछ को मिलती है और वो जिम्मेदारी लेते हैं बाकी सबको बोट डलवाने की। फिर आपका अपना कोई बजूद नहीं बचता, उनकी नजरों में आप सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाते हैं।

और अपने क्षेत्र के लिए काम की मांग करना एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। बरना आप उनके लिए एक भेड़चाल वाला समृद्ध और उसकी एक संख्या बनकर रह जाएंगे। आजकल हर तरफ नफरत का बाजार लगा है। एक धर्म के ठेकेदार अपने लोगों को बताते हैं की तुम खतरे में हो इसलिए एक पार्टी को बोट दो। दूसरे धर्म के ठेकेदार अपने लोगों को कहते हैं की तुम खतरे में हो तो एक पार्टी को हराने के लिए बोट दो। यहीं से बोटों का एकत्रीकरण करवाया जाता है और समझिया जाता है की अपना दिमाग मत लगाओ जो ठेकेदार कह रहे हैं वो ही करो। फिर नेता हमें 80-20 में बांटने की बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता, वो हम लोगों को सिर्फ एक संख्या ही मानते हैं कि या तो 80 में आ जाओ या 20 में आ जाओ। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाने पर पता चलता है की लोग बहुत अधाव में जी रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में अभी विकास नाम की चिड़िया ने पर भी नहीं मारा है। ऐसे ही लोगों से बात करिए तो लोग रोजर्मार्झर में होने वाली समस्याएं बताते हैं जैसे पानी के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, घंटों बिजली नहीं आती है, स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है। दाल, तेल, आटा, चावल, मसाले ये सब बहुत महंगा हो गया है, सिलेंडर घर में तो है लेकिन भरा नहीं पा रहे क्योंकि गैस बहुत महंगी है और कमाई या तो है नहीं और अगर है तो बहुत कम। बेरोजगारी और महंगाई तो चरम पर है ये बात तो सरकारी डाटा भी बताते हैं। अच्छी बात ये है कि लोग इस बात को जानते हैं कि उन्हें जरूरत है बुनियादी सुविधाओं की और ये बुनियादी सुविधाएं सरकार के जरिए ही आयेंगी। लेकिन वहीं खराब बात भी है की जब सरकार बनाने के लिए बोट डालने का समय आता है तब बोट डालते हैं जाति, धर्म, कुछ रुपए, दार्शन, मेरे जाने वाला खड़ा है या भ्रामक प्रचार वाला बातों में आकर। जब आप ये करते हैं तब आप उन्हें ये बता रहे हैं कि आपको काम नहीं चाहिए सिर्फ यहीं सब चाहिए और किसी ठेकेदार के जरिए आपको सिर्फ एक संख्या की तरह ही गिना जाए इससे ज्यादा नहीं। न्यूज मीडिया के दौर में नेताओं को हीरो बनाया जाता है और बनाना भी चाहिए क्योंकि वो जनता के लिए बहुत काम करते हैं। आप बिल्कुल नेताओं को हीरो बनाइए। लोग सलमान, शाहरुख के फैन हैं लेकिन अगर पिंकर में काम अच्छा नहीं है तो कुछ दिनों के बाद लोग देखने नहीं जाते और वो पिंकर पिट जाती है। ठीक ऐसे ही नेता के फैन बनिए पर दिमाग खुला रखिए। उनकी बातें और काम दोनों पर नजर बनाए रखिए। मीडिया में दिखाया जाने वाला हवाबाजी वाला नहीं क्योंकि वहाँ तो नंबर्स को इंधर-उधर कर के आपको बरगलाया जाएगा, धरातल वाला काम देखिए, अपने आस पास देखिए और समझिए। बरना किस जगह किसी नेता के कितने फैन है आप इसी संख्या भर रह जाएंगे। वे आपको संख्या न माने, इसलिए सोचिए। जब आप अमीबा से मानव बने तो उसके साथ-साथ दिमाग और दिल दोनों विकसित हुए। इसलिए थोड़ा अपने अहसास से समझिए, दिमाग को चलाइए और समय समय पर तंत्र को, समाज को, सरकारों को, संस्थाओं को, पार्टीयों को, बड़े-बड़े उद्योगों को ये याद दिलाते रहिए की आप मानव हैं सिर्फ एक संख्या नहीं।

साइबर अपराधियों से बचाना होगा युवाओं को

कुलांचे भरते शेयर बाजार व सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दावों के बीच एक स्थान सह यह है कि भारतीय युवा सुनहरे सपनों की आस में दुनिया भर में गाए-मारे फिर रहे हैं। उससे भी ज्यादा दुखद यह कि वे बिलियों, दलालों व अपराधियों की साजिश से मानव तस्करी और साइबर अपराधों का शिकार बन रहे हैं। सुनहरे सपने दिखाने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों से सम्मोहित होकर हमारे युवा ऐसे आपराधिक जाल में फँस जाते हैं कि वहां से उनका देश लौटना भी संभव नहीं होता। हमारे देश की काली में इस साजिश का हिस्सा होती है। भारत के हजारों युवा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फँसे हैं और साइबर अपराध करने वाले नियोक्ताओं के चंगुल में फँसकर अवैध गतिविधियों को संचालित करने को मजबूर हैं। यह तथ्य भी कम चिंताजनक नहीं है देश में साइबर अपराध में लिप्त लोग ही हमवतन लोगों को संदिग्ध क्रिटोकरेंसी योजनाओं में निवेश करने को लुगा रहे हैं। जनवरी 2022 से मई 2024 तक विजिटिंग वीजा पर कंबोडिया, थाइलैंड, म्यांगांग और वियतनाम की यात्रा करने वाले 73000 भारतीयों में 30,000 अग्री तक वापस खदेश नहीं लौटे हैं। इनमें से आधे से अधिक साइबर गुलाम 20 से 39 वर्ष आयु वर्ग के हैं। उल्लेखनीय है कि इन लापता युवाओं की राज्यवाद सूची में पंजाब शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का आंकड़ा है। निश्चित तौर पर यह हमारे नीति-नियंत्रणों की विफलता है कि अपने बच्चों को देश में उनकी आकांक्षाओं के अनुसुध्य रोजगार देने में विफल है। सौम्यांग से भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आवादी मिली है मगर हम उन्हें उम्मीदों के अनुसुध्य काम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं यह हमारी कानून व्यवस्था व खुफिया तंत्र की विफलता भी है कि हमारे बच्चे आसानी से साइबर अपराध करने वाले गिरोहों के चंगुल में फँस जाते हैं। हाल ही में कुछ भारतीय युवाओं को म्यांगांग के साइबर अपराधियों के अड्डे से मुक्त कराया गया था। इस साजिश के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्यवाई करने की जरूरत है। ऐसे हालात में अपराध नियंत्रण हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इस संज्ञाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि साइबर अपराधी भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फँसा सकें। यहां सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल किए हुए हैं तो हमारी युवा प्रतिभाएं अन्य विकासशील देशों में नौकरी करने को क्यों मजबूर हो रही है? ये हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था वाली छवि के विपरीत है। यदि गौजूदा समय में हम अपने देश में कुशल युवाओं को उनकी जरूरतों व आकांक्षाओं के अनुसुध्य नौकरी देने में विफल रहते हैं तो विकसित भारत का लक्ष्य दूर की कौड़ी बनकर रह जाएगा।

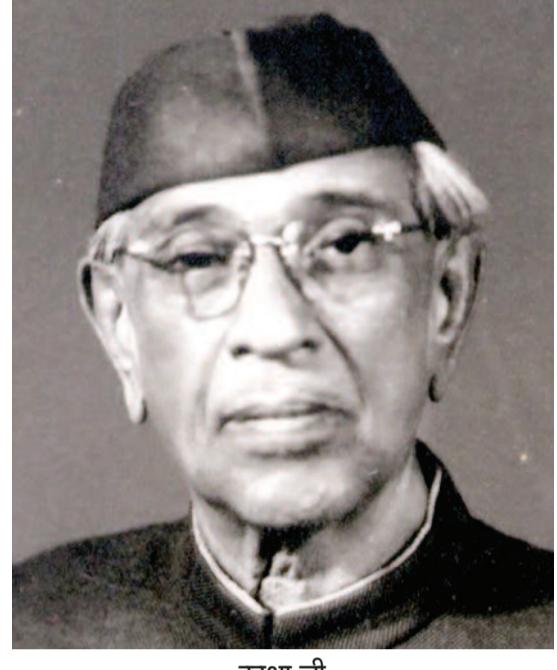
दलित, सर्वजनिक, छुआछूत और राजनेता



प्रविन बग्री



सीताराम



बिजु पट्टनायक

फो ये में जो दिख रहे हैं इनका नाम है सीताराम। ये दलित हैं। मजबूती करते हैं। भेद खेत भी बढ़ावे पर बोते हैं। इनके पिता राम यार यूपी के थे। बिहार के एक चीनी मिल में सीजनल कर्मचारी थे। वहां मेरे परिवार के संपर्क में आए। मेरे परबाबा ने इन्हें गांव लाकर अपनी जमीन पर बसाया। अब न मेरे परबाबा है न रागु जी, लैकिन उनके पुरुष और उनका परिवार अब भी उसी जमीन पर रहता है। पहले ज्ञापांडी थी। अब पक्का मकान बन गया है सीताराम जी भी दादा-नाना बन गए हैं। लैकिन अब भी उनके परिवार से घर का बही संबंध है, जो पूर्वजों के साथ था। गांव

गांधी महीनों - महीनों तक दिल्ली की दलित बस्ती में रहते थे। आज कितने गांधी भक्त दलित बस्ती में झांकने भी जाते हैं? स्व. बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ आंदोलन के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए जितना किया उतना नहीं किया। पाठक जी ब्राह्मण थे। एक और घटना मुझे याद आती है। यह घटना सभवत: 1987 - 88 की है। गया जिले में कोई गांव था (नाम याद नहीं आ रहा), उस गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। गांव भूमिहार बहुत था। अब किस दिन भी जिले में अनेक दलित परिवार थे। उन्हें गांव के मर्दिंगे प्रवेश नहीं करने दिया जाता था।

वालों ने पिछले पंचायत चुनाव में उन्हें पंच चुना था।

पहले वे ज्ञापांडी में रहते थे। अब पक्का मकान है। मेरे युवाव्यवस्था तक सीताराम यांव में हांसेर घर आते थे तो जमीन पर बैठते थे। कभी उन्हें चौकी, खटिया या कुर्सी पर बैठते नहीं देखा। लैकिन इस बार जब मैं गांव गया तो देखा कि वे अब कुर्सी पर बैठे रहे हैं। पूरे गांव में किसी को इस पर आपत्ति नहीं है। पिछली बार श्रावणी पूजा में मैं परिवार सहित गांव गया था, तब अपनी पत्नी से इनका परिचय कराया। पत्नी ने स्वाभाविक संस्कार वाले उनके पैर छूते प्रणाम किया। बेचों सीताराम जी सकुर्सी पर आपत्ति नहीं है।

यह प्रसंग सार्वजनिक करना इसके अनुसुध्य रोजगार देने में विफल है।

पिछली बार श्रावणी पूजा में मैं परिवार सहित गांव गया था, तब अपनी पत्नी से इनका परिचय कराया। पत्नी ने स्वाभाविक संस्कार वाले उनके पैर छूते प्रणाम किया। बेचों सीताराम जी सकुर्सी पर आपत्ति नहीं है। यह प्रसंग सार्वजनिक करना इसके अनुसुध्य रोजगार देने में विफल है। उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

यह प्रसंग सार्वजनिक करना इसके अनुसुध्य रोजगार देने में विफल है।

उनके बारे में कहे गए थे।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बारे में कहे गए।

उनकी जाली की गांव के चंगुल में अपनी पत्नी को इसकी विफलता के बार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 17 अंक 195

बाजार की सहजता

बा जार नियमक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की बोर्ड बैठक में नियमन में कई बदलावों की घोषणा की गई। सेबी चेयरपरमान के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों और खराब कार्यसंस्कृति के आरोपों के बीच नियमक काफी दबाव में था। ये दोनों ही विषय बोर्ड मीटिंग के एंजेंडे में नहीं थे।

बोर्ड ने कई बदलाव पेश किए। उदाहरण के लिए म्युचुअल फंड के लिए एक नई प्रसंसंपत्ति श्रेणी और पैसिव स्कीम के लिए अपेक्षाकृत हल्के मानक पेश किए गए। पैसिव स्कीम में वे म्युचुअल फंड आते हैं जो मानक संचाकों का अनुकरण करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सेबी का ध्यान कारोबारी सुभास्ता बढ़ावा पर है। नियमक के बकाव्य में इसका इस्तेमाल कई बार किया गया। यो उपाय अपनाए गए हैं उनमें से कई प्रतीत में मशविरा पत्रों के माध्यम से चर्चा की जा चुकी है। सेबी के बोर्ड ने कम खुलासों, राइट इश्यू के लिए तेज प्रक्रिया, टी प्लस 0 सेटलमेंट (शेयरों के कारोबार का उसी दिन निपटन) का विस्तार और टी प्लस 0 सेटलमेंट साइकिल के तहत ब्लॉक हुए सौंदर्यों के लिए वैकल्पिक प्रणाली आदि पर सहमति जताई। उसने भेदिया कारोबार नियमन की रोकथाम का दायरा बढ़ाया। खुदरा निवेशकों को यह इजाजत होगी कि वे एकीकृत भुगतान इटरफेस ब्लॉक व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकेंगे जो प्राथमिक इश्यू के लिए रोकी गई राशि समर्थित ऐलोकेशन (एसबीए) के समान होगी।

उदाहरण के लिए नई परिसंपत्ति श्रेणी ('निवेश रणनीति') को पहले चर्चा की जा चुके ढांचे के अधीन रखा जा रहा है। इसका इरादा पारंपरिक म्युचुअल फंड और पॉर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के बीच के अंतर को पाठाना है। 10 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा तय करके वह यह सुनिश्चित करने का काम करेगी कि केवल अपेक्षाकृत अमीर निवेशक और जीवित ले सकने वाले ही भागीदारी कर सकें। इससे गैर पंजीकृत योजनाओं को बाजार से बाहर करने में मदद मिलेगी। म्युचुअल फंड लाइट के ढांचे पर भी चर्चा हुई। यह विशुद्ध संपत्ति, पुनर्नेप्रदान और प्रायोजकों के मुनाफे की आवश्यकता को कम करके नए कारोबारियों के लिए पैसिव प्रबंधन वाले फंड में प्रवेश आसान बनाता है। न्यासियों पर अनुपालन का अधिक बोझ नहीं होगा और पैसिव योजनाओं की शुरुआत के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सुसंगत बनाया जाएगा। इससे प्रतिवर्ध्या और निवेशकों के समक्ष निवेश विकल्प बढ़ेंगे। एक राइट इश्यू की प्रोसेसिंग की अवधि को कम करके अधिकतम 23 कार्य दिवस किया जा रहा है जो पहले औसतन 31.7 दिन होती थी। इससे अतिरिक्त फंड जुटाने में मदद मिलेगी। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कई खुलासों को मानों को खोला जाना चाहिए। यह विशुद्ध संपत्ति के लिए एकल फाइलिंग सदस्य होने की है ताकि प्रासंगिक रिपोर्ट, दस्तावेज आदि को एक एक्सचेंज पर फाइल किया जा सके।

अगर बोर्ड मीटिंग का कारोबारी अवधि के बाद समाप्त होती है तो मीटिंग के नतीजों को जारी करने की अवधि को 30 मिनट से बढ़ाकर तीन घंटे कर दिया गया है। किसी सूचीबद्ध कंपनी के खिलाफ दावों से जुड़े मुकदमे या विवाद के प्रकटीकरण के लिए 24 घंटे के बजाय 72 घंटे का समय दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी सूचना को डिजिटल डेटाबेस में बनाकर रखा जाए। यह समझौते भी भद्र बदलाव है।

संबद्ध व्यक्ति की परिभाषा को विस्तार दिया गया है जिससे भेदिया कारोबार नियमन का दायरा बढ़ेगा। अब इसके दायरे में कई और लोग आएंगे। उदाहरण के लिए किसी संबद्ध व्यक्ति के साथ आवास साझा करने वाला व्यक्ति या किसी संबद्ध व्यक्ति की भागीदारी वाली फर्म में भागीदार या कर्मचारी व्यक्ति को भी इसके दायरे में रखा जाएगा जो प्रोक्षण रुप से किसी भी तरह प्रतिभूत बाजार से संबद्ध है। यह दायरा बहुत व्यापक है और देखना होगा कि यह हीकोकत में कितना कारगर साबित होता है।



इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक कचरे के पुनर्वर्तन के लिए सरकार को ठोस नीति बनाने से अपरिवर्तित होता है।

परंतु यह मूल्यांकन सही नहीं है क्योंकि इसके अनुसार मूल्यांकन धूतुओं का मूल्य 2 रुपये प्रति किलो आता है जो अखबार की रक्षी 15 रुपये प्रति किलो से भी बहुत कम है। यह सब कहने का तात्पर्य

माइक्रोफाइनैस क्षेत्र में नए दौर की शुरुआत

बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई और फिनटेक कंपनियां कर्ज लेने वालों को लुभाने और कर्ज देने पर तुली हुई हैं। बता रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

सू

चीबद्ध माइक्रोफाइनैस कंपनी

इस्यूजन फाइनैस लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि फंसे हुए रुपयों में इजाफे को देखते हुए उसे 2024-25 की सिंतंबर तिमाही में 500-550 करोड़ रुपये अलग खर्चे पड़ सकते हैं। पहली तिमाही में प्यूजन ने 348 करोड़ रुपये अलग रखे थे, जिसे प्रोविजनिंग भी कहते हैं। 21 सिंतंबर को स्टॉक एक्सचेंजों को दी सूचना में फ्यूजन ने कहा, 'वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद से कंपनी का प्रबंधन इस बात पर नज़र रख रहा है कि कर्ज लेने वाले उसे चुकाने किस तरह है।' कर्ज चुकाने के रुपाने तिमाही के नतीजे जारी की जा रही तिमाही के 500 करोड़ से 550 करोड़ रुपये तक का कर्ज फंस सकता है, जिसके लिए उसे प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। फंसे कर्ज लेने वाले खाटे व्यक्तियों को स्लाइड संख्या 8 दिखाने के बाद कही। आखिर इस स्लाइड में क्या था?

स्लाइड के मुताबिक मार्च 2023 में प्यूजन के कुल ग्राहकों में से 'यूनाइट' यानी कर्ज लेने वाले ग्राहकों की उनकी क्षमता भी नहीं है। इसका असर हमारे पोर्टफोलियो पर दिखा है क्योंकि कुछ कर्जदार बार-बार कहने पर तो यह बदला चुका है।

उन्होंने यह बात विशेषज्ञों को स्लाइड में क्या था?

स्लाइड के मुताबिक मार्च 2023 में प्यूजन के कुल ग्राहकों में से 'यूनाइट'

कर्ज लिए हैं, जिन्हें चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है। इसका असर हमारे पोर्टफोलियो पर दिखा है क्योंकि कुछ कर्जदार बार-बार कहने पर तो यह बदला चुका है।

उन्होंने यह बात विशेषज्ञों को स्लाइड में क्या था?

स्लाइड के मुताबिक मार्च 2023 में प्यूजन के कुल ग्राहकों में से 'यूनाइट'

कर्ज लेने वाले ग्राहकों की क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।

यह उदाहरण के कार्यक्रम के लिए चुकाने की उनकी क्षमता भी नहीं है।



आस्था पर सियासत

ति स्पष्ट मंदिर लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आंश्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नायडू ने दावा किया था कि बिहारी सरकार के दीरान तिपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल बिना गर्भ शुद्ध होने की बजाय जनरों की चर्चा से युक्त था। अदालत का सवाल है कि जांच जारी है तो रिपोर्ट आने से पहले आप में दिया गए। लड्डू का खाद्य खारब होने की श्रद्धालुओं की शिकायत की बात उन्हें पर राज्य सरकार से सवाल किया कि आप कह सकते हैं कि टेंडर गत तरीके से दिया गया, मगर यह कहना कि मिलावटी घी प्रयोग किया गया, इसका सबूत कहाँ है। सबसे पहले आंश्र प्रदेश के सेंचुरालाम पर्वत पर स्थित तिस्तमा तिरुप्ति देवस्थानम के अधिकारी ने शुद्ध घी में बनसपति तेल की मिलावट की बात उठाई। बात में इसमें जनवरों की चर्चा होने की बात कर उन्हें विवाद पैदा किया। नायडू सरकार द्वारा दाव किया गया कि प्रसाद में छहती की तरत और बीफ चर्चा की इस्तेमाल परीक्षण के नमूनों में पाया गया। हालांकि यह लड्डू मंदिर परिसर की गुप्त रसेंट पौट में बड़ी संख्या में तैयार किया जाता है। यही पवित्र लड्डू रोजे हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर पहले मुफ्त दिया जाता था, बाद में विभिन्न नियमों के साथ इसकी कीमत तय कर दी गई। यह बहुसंख्य देवशास्त्रियों की आस्था से जुड़ा मामला है। हालांकि तकलीन मुख्यमंत्री जनमोहन रेडी ने चंद्रबाबू पर राजनीति के लिए भगवान का प्रयोग करने और जनता का ध्यान सरकार के कामों से हटाने का आधार लागाया। मंदिर की पवित्रता को ठेस लाने वाली खेड़े और श्रद्धालुओं के लिए किसी सदैरी से कम नहीं कही सकती। मराठा शीर्ष अदालत ने कहा है कि धर्म को राजनीति से मिलाने की जरूरत नहीं है। आस्था-विवाद के प्रति राजनीतियों को विशेषता बरतनी सीखनी चाहिए। राजनीतिक लाभ के लाभ में धर्म का दुर्योग, जनता को दिव्यमित करने और समुदायों के द्रम्यान दरवरें डालने वालों पर सख्ती की जानी आवश्यक है। सनसनी फैलाने वाले दोषमुक्त नहीं हो सकते। यदि वास्तव में किसी भी तरह की मिलावट हुई है, तो आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बुखान नहीं जाना चाहिए।

महायुद्ध की आशंका

प्रथम एशिया में रीबी 1 वर्ष से जारी संघर्ष अब दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। इसाइल के हाले में लेवाना में हिजबुल्लाह के नसरल्लाह और उसके नंबर दो अली कराकों के मरे जाने के बाद इस संघर्ष के महायुद्ध में तबदील होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसाइल के प्रधानमंत्री बीजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचारी की। दोनों नेताओं के बीच मध्यम परिषद के विस्तार होने की बात उपर्युक्त विवाद के हालात पर चर्चा हुई। इसाइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष के विस्तार होने की आशंकाओं के मद्देनजर यह जानीत बेहद महत्वपूर्ण मारी जा रही है। मोदी ने अपनी इसाइली समकक्ष से कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। वस्तुतः हमास के प्रमुख ने इसाइल हानिया की हत्या के बाद नसरल्लाह के मारे जाने के बाद परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। सबसे अधिक चिंताजनक रिपोर्ट यह हो सकती है कि ईरान, हासास, इराक, हिजबुल्लाह और सेरिया में सक्रिय इसाइल सरकार की हावियारबंद यूट भिलरक इसाइल पर हमला बोले, जिसके जबाब में इसाइल की ओर से कई देशों में एक साथ सैनिक करारवाई की जाए। इस मुहूर्में इसाइल को अमेरिका, ब्रिटेन सहित कुछ अन्य यूरोपीय देशों की ओर से सक्रिय समर्थन मिलेगा। सबसे भयावह परिदृश्य परिचम एशिया में महायुद्ध का हो सकता है। इसके विश्व युद्ध में तबदील होने की आशंका ही सही लेकिन आशंका कहा। ऐसा परिदृश्य उस समय बनेगा जब इसाइल के परमाणु क्रेनों को नष्ट करने के अपने पुरुषे मंसूबे पर अमल करने का दुस्साहस करा। वास्तव में इसाइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा इरान को मानता है। इसाइली समकक्ष नेतन्याहू ने सोमवार को इरान के लोगों से कहा कि हर दिन आप के एक ऐसी शासन को देखते हैं कि अमरीका ने अपनी नंबर दो लेता है। अगर उन्हें अपनी पराह तो वह मध्य पूर्व में बेवजह के युद्धों पर अबी डांबर बाबू करना बंद कर देगा। इसाइल को इस हकीकत का पता है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे पश्चिमी एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। यह इसाइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। मध्य-पूर्व की राजनीतिक अस्थिरता भारतीय हितों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी शांति और स्थिरता के लिए युद्धरत दोनों पक्षों से संवाद कर रहे हैं।

शास्त्री जयंती/श्वेता गोयल

नैतिकता की मिसाल

भा रत के प्रधानमंत्री बनने से पहले लालबाहु शास्त्री भारत सरकार में दिव्यांशु, गृह मंत्री और रेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पर संभाल चुके थे। एक बार वे रेल के एसी कोच में सफर कर रहे थे। उन्हें दीरान वाले यात्रियों की समस्या को जीवन लाया है। उसी समय की बात है, जब लालबाहु शास्त्री जेल में थे। उसी दीरान पर त्रिप्यक्ष अनुभव किया कि यात्रियों को जीवनीय दिलचस्पी की जाए। उसी दीरान वाले यात्रियों को खानपान की सुविधा उपलब्ध करने के लिए खेड़ी की सुविधा भी उन्होंने शुरू करवाई।

स्वतंत्रता सम्प्राप्त के दीरान 1940 के दशक में लालबाहु शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री देशों की अर्थव्यवस्था और सोसायटी के विवरों को जीवन लाया है। उसी समय की बात है, जब लालबाहु शास्त्री जेल में थे। उसी दीरान वाले यात्रियों की समस्या को जीवनीय दिलचस्पी की जाए। उसी दीरान वाले यात्रियों को खानपान की सुविधा भी उन्होंने शुरू करवाई।

पली का यह जावा मिलाने के बाद शास्त्री जी ने संस्था को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ध्यावद देते हुए कहा कि अगली बार से उनके परिवार को केवल चालास रुपये ही भेजे। जाएं और उन्हें दीरान पर रुपये से किसी और जस्तरामें की सहायता कर दी जाए। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री रहने भारत और पाकिस्तान को युद्ध हुआ तो देशवासियों में हासला बनाया रखने के लिए उन्होंने जय जवान कियान का उद्योग किया। दो अक्टूबर, 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लालबाहु शास्त्री की जाज हम 120वीं जयंती मना रहे हैं, जिनकी 11 जनवरी 1966 की रात मौत हो गई थी। उनके पद्धतिगतों पर चलाने का संकल्प लाना ही सच्चे अर्थों में उन्हें हमारी श्रद्धांजलि होगी।

वित्तीय अनुमान प्रह्लाद सबनानी

आज विश्व में कई विकासित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न प्रकार की आंशिक चिंताओं के साथ विश्व कर्तव्य विवरण करते हैं।

आज विश्व में कई विकासित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न प्रकार की आंशिक चिंताओं के साथ विश्व कर्तव्य विवरण करते हैं।

विश्व में कई विकासित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न प्रकार की आंशिक चिंताओं के साथ विश्व कर्तव्य विवरण करते हैं।

पली का यह जावा मिलाने के बाद शास्त्री जी ने संस्था को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ध्यावद देते हुए कहा कि अगली बार से उनके परिवार को केवल चालास रुपये ही भेजे। जाएं और उन्हें दीरान पर रुपये से किसी और जस्तरामें की सहायता कर दी जाए। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री रहने भारत और पाकिस्तान को युद्ध हुआ तो देशवासियों में हासला बनाया रखने के लिए उन्होंने जय जवान कियान का उद्योग किया। दो अक्टूबर, 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लालबाहु शास्त्री की जाज हम 120वीं जयंती मना रहे हैं, जिनकी 11 जनवरी 1966 की रात मौत हो गई थी। उनके पद्धतिगतों पर चलाने का संकल्प लाना ही सच्चे अर्थों में उन्हें हमारी श्रद्धांजलि होगी।

पली का यह जावा मिलाने के बाद शास्त्री जी ने संस्था को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ध्यावद देते हुए कहा कि अगली बार से उनके परिवार को केवल चालास रुपये ही भेजे। जाएं और उन्हें दीरान पर रुपये से किसी और जस्तरामें की सहायता कर दी जाए। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री रहने भारत और पाकिस्तान को युद्ध हुआ तो देशवासियों में हासला बनाया रखने के लिए उन्होंने जय जवान कियान का उद्योग किया। दो अक्टूबर, 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लालबाहु शास्त्री की जाज हम 120वीं जयंती मना रहे हैं, जिनकी 11 जनवरी 1966 की रात मौत हो गई थी। उनके पद्धतिगतों पर चलाने का संकल्प लाना ही सच्चे अर्थों में उन्हें हमारी श्रद्धांजलि होगी।

पली का यह जावा मिलाने के बाद शास्त्री जी ने संस्था को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ध्यावद देते हुए कहा कि अगली बार से उनके परिवार को केवल चालास रुपये ही भेजे। जाएं और उन्हें दीरान पर रुपये से किसी और जस्तरामें की सहायता कर दी जाए। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री रहने भारत और पाकिस्तान को युद्ध हुआ तो देशवासियों में हासला बनाया रखने के लिए उन्होंने जय जवान कियान का उद्योग किया। दो अक्टूबर, 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लालबाहु शास्त्री की जाज हम 120वीं जयंती मना रहे हैं, जिनकी 11 जनवरी 1966 की रात मौत हो गई थी। उनके पद्धतिगतों पर चलाने

बुलडोजर और न्याय

देश भर में 'बुलडोजर कार्रवाई' को लोकर जारी बहस के बीच 'जमीयत उलोमा-ए-हिंद' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला तो सुरक्षित रख लिया, मार मामले की सुनवाई के दैशन की गई उसकी टिप्पणियां कुछ कम मानी खेज नहीं हैं। अदालत ने न सिर्फ यह कहा कि किसी के आरोपी होने या दोषी करार दिए जाने पर भी उसकी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, बल्कि अंतिम आदेश तक ऐसी कार्रवाईयों पर रोक लगाते हुए उसने यह भी साफ किया कि किसी अतिक्रमण को गिराए जाने से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए और इसके दस्तावेजी सुबूत भी होने चाहिए। यानी लक्षित संपत्ति पर नोटिस दियकाने के साथ रोजटर्ड डाक से भी इसे भेजा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बी अकर गवर्नर और केवी विश्वनाथन की छंडपोठे ने अपने अंतिम फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साफ सेंकें दिए हैं। उम्मीद है, इसके बाद किसी किस्म की गफलत या बनायी रखी के लिए नियम गुन्जाइश नहीं रहेगी।

उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णयक फैसला आने के बाद बुलडोजर की राजनीति पर लगाम लगेगी और प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकेगी।

इसके कार्रवाईयों के लिए देश में सार्वजनिक कार्रवाई के अतिक्रमण और उन पर अवैध निर्माण की बेशुमार घटनाएँ हैं और अदालत ने इस मामले में राज्य प्रशासन को कानून-सम्पत्त कदम उठाने और ऐसी जगहों को खाली कराने की छूट पहले ही दे रखी है। मगर विंडबना यह है कि किसी खाली कराने की छूट पहले ही दे रखी है। अपराध और जरूरत विवाह की खबरें आई थीं। ताकिरेवन को होटा का सारा हिंदू समाज जान बचाने के लिए वहां से गोलपंथी की ओर चल पड़ा था। गांधीजी उस समय अहमदाबाद में थे और दिल्ली में उका मुकाम था विस्तृत नेता मौलाना मोहम्मद अली का दरियांज वाला मकान। वहां से उड़ाने अपने अधिन साधी सरराम वल्लभभाई पटेल को खत्त (गुजराती) में लिखा- 'भाई श्री वल्लभभाई, मेरा फैसला आपको यह खत देता हूँ, उससे खलाम हो जाएगा। आप बव्वर शेर हैं और... आप घबरायेंगे नहीं। मेरा इशारा है कि मेरा अनशन वहीं पूरा होगा...'। गांधीजी ने दो दिन बाद अपना फैसला देश के सामने रखा। मौलाना मोहम्मद अली से कहा, 'मेरे फैले से आपको पीड़ा होगी। मैं जानता हूँ, आप अपने को सालगिरहे। अपकी आंखों में अंसु देख खूँ खूँ ठूट सा जांगला।'

किसी भी अवैध निर्माण को गिराने की एक तय प्रक्रिया होती है, जिसके तहत कार्रवाईयों सुखदार लोगों के विरुद्ध भी ही है। नोएडा में दिवान टावर को गिराए जाने की बात बहुत उम्मीद है। मगर किसी व्यक्ति के आपराधिक क्रूरत की दृष्टि की साथ पूरे परिवार को देना नैरापक न्याय के विरोध है। इसलिए शीर्ष अदालत ने यह संकेत किया है कि प्रशासन ने अवैध तोड़-फोड़ की कार्रवाई की, तो पीड़ित को संवित वापस करनी पड़ेगी। अगर रोडमैप में यह बात स्पष्टता से समान आई, तो आईदा अधिकारी व सत्तारूढ़ राजनेता फौरन बुलडोजर निकालने से पहले कई बार सोचें। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करने की पुख्ता व्यवस्था होनी ही चाहिए। न्यायप्रय व्यवस्थाओं में कानून नागरिकों के संरक्षण के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गिराया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध निर्माण को गिराने के विरुद्ध भी ही है। नोएडा में दिवान टावर को गिराए जाने की बात बहुत उम्मीद है। मगर किसी व्यक्ति के आपराधिक क्रूरत की दृष्टि की साथ देश-तुनिया में यही संदेश गया कि अल्पसंखक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में, जयज कार्रवाईयों भी संदेह के घेरे में आ गई। शीर्ष अदालत ने उचित ही यह स्पष्ट किया है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और वहां पर अपाराधिक कानून धर्म से प्रेरित नहीं हो सकते। अवैध निर्माण चाहे जिस भी धर्म से वाचस्ता हो, उसे हटाया ही जाना चाहिए।

किसी भी अवैध निर्माण को गिराने की एक तय प्रक्रिया होती है, जिसके तहत कार्रवाईयों सुखदार लोगों के विरुद्ध भी ही है। नोएडा में दिवान टावर को गिराए जाने की बात बहुत उम्मीद है। मगर किसी व्यक्ति के आपराधिक क्रूरत की दृष्टि की साथ पूरा समाज देश-तुनिया में यही संदेश गया कि विरुद्ध अदालत ने यह संकेत किया है कि प्रशासन ने अवैध तोड़-फोड़ की कार्रवाई की, तो पीड़ित को संवित वापस करनी पड़ेगी। अगर रोडमैप में यह बात स्पष्टता से समान आई, तो आईदा अधिकारी व सत्तारूढ़ राजनेता फौरन बुलडोजर निकालने से पहले कई बार सोचें। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करने की पुख्ता व्यवस्था होनी ही चाहिए। न्यायप्रय व्यवस्थाओं में कानून नागरिकों के संरक्षण के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गिराया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गिराया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध नि�र्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध निर्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध निर्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गि�राया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध निर्माण को खोखाकरने के लिए होते हैं। जब किसी का घर कोई अन्य स्थानीय निर्माण गिराया जाता है, तब उससे न सिर्फ उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उसकी सामाजिक क्षति भी होती है। एक बुलावादी समाज में इससे दीर्घकालिक विलगाव पैदा होता है। हिमाचल की घटना एक ताजा मिसाल है। वहां एक मस्तिज में अवैध निर्माण

योजना और लक्ष्य के बीच अनुशासन सबसे अहम कड़ी है

बुलडोजर कार्रवाई

यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर दिशानिर्देश जारी करने की बात कहते हुए यह भी कहा कि मंदिर हों या दर्शाह, उनका निर्माण सँझक पर नहीं किया जा सकता। बिंबना यह है कि सड़कों के साथ रेलवे ट्रैक और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाता है। यह किसी से डिया नहीं किया किसका आवश्यकारी या निजी भूमि पर कब्जे के लिए धार्मिक स्थलों का अवैध निर्माण किया जाता है। अब तो इसकी चेपट में बन भूमि भी आ रही है। चूंकि आस्था के नाम पर ऐसे अवैध स्थलों को हटाने से बचा जाता है, इसलिए उनका निर्माण बेरोक-टोक जारी है। तथा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले यह आदेश दिया था कि यातायात में बाधक बनने वाले धार्मिक स्थलों को हटाया जाए, लेकिन उस पर अमल अब तक नहीं किया जा सका है। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि ऐसा क्यों है? अवैध तरीके से अधब कार्रवाई कर बनाई गई इमारतों के खिलाफ सख्ती दिखाई ही जाना चाहिए। इसी से अतिक्रमण और अवैध निर्माण की राष्ट्रज्यामी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस समस्या के लिए केवल अवैध निर्माण या अतिक्रमण करने वाले ही दोषी हीं। इसके लिए सकारी विभाग भी दोषी हीं, जो नियम विरुद्ध निर्माण होने देते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए, जिससे देश में अवैध निर्माण थमे-वह चाहे धार्मिक स्थलों के रूप में हो या फिर अन्य किसी तरह के निर्माण के रूप में।

बीते कुछ समय में बुलडोजर कार्रवाई पर इसलिए स्वाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में संगीन अपराधों में लिप्त अभियुक्तों के घरें, दुकानों अदि पर बुलडोजर चलाए गए। इस पर संघर्षित सकारों और उनके पुलिस-प्रशासन की ओर से यह दलील दी जाती है कि इस तरह की कार्रवाई किसी व्यक्ति के अपराध में लिप्त होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए की जाती है कि उसका घर या व्यावसायिक स्थल बिना नक्शे के या अतिक्रमण करके बना पाया गया होता है। यह दलील निराधार नहीं, लेकिन सच यह है कि अपने देश में बड़ी संख्या में घर और अन्य इमारतें स्थानीय निकायों की ओर से स्वीकृत नक्शे के बिना बनाई जाती हैं। यह भी एक सच्चाई है कि जिस इलाके में किसी सौंदर्य अपराधी या अभियुक्त का घर अथवा व्यावसायिक भवन अवैध तरीके से बना होता है, वही अन्य लोगों की भी बने होते हैं, लेकिन वे बुलडोजर कार्रवाई के बारे में बचे रहते हैं। इसी कारण अनविवत निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के जरिये जब किसी अभियुक्त का घर गिराया जाता है तो उसके स्वतन्त्र भी सड़क पर आ जाते हैं। यह भी न्यायसंगत नहीं। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पहल को भी देखेगा और अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को भी सहन नहीं करेगा।

नशामुक्त हिमाचल

हिमाचल प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या से हर वर्ष चिंतित है। राज्य में नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अब तो इसके कारण युवाओं की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। नशे के विरुद्ध कई अभियान चलाए जाने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पाया रही है। फले कम मात्रा में चिट्ठे, चरस एवं अन्य नशीले पदार्थों की बरामदगी हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय में युवाओं का एक बर्ग अत्यधिक मृत्यु-संस्कृतिक पदार्थ के रूप में हो रहा है। चिंता इस बात की है कि प्रदेश की युवा पोर्पी नशों के दलदल में धंसती जा रही है और उसे बचाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चिट्ठे की आपूर्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने आवश्यक हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश स्कूलों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के जरिये जब किसी अभियुक्त का घर गिराया जाता है तो उसके स्वतन्त्र भी सड़क पर आ जाते हैं। यह भी न्यायसंगत नहीं। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पहल को भी देखेगा और अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को भी सहन नहीं करेगा।

नशे की गंभीर
होती समस्या को
रोकने के लिए
प्रदेश में व्यापक
अभियान चलाना
समय की मांग है

नशे की गंभीर
होती समस्या को
रोकने के लिए
प्रदेश में व्यापक
अभियान चलाना
समय की मांग है

सूखे की चपेट में अफ्रीका

बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया,
मलावी, जांबिया, जिंबाब्वे के लोगों
पानी, भोजन और आजीविका के
खतरे से जूझ रहे हैं

की भयावहन इतनी है कि नामीबिया की लगभग सभी प्रमुख फसलें नष्ट हो चुकी हैं। चारों की गंभीर कमी और तापमान में वृद्धि के कारण मवेशी मर हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, नामीबिया के लगभग 84 प्रतिशत खाद्य संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके हैं, जिससे देश में व्यापक खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है। यह किसी को पूर्णतः बास्तविक नहीं है, जो जंगलों के माध्यम से अधिकतम देश के लोगों को खाना देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है। ऐसे किसी के लिए जंगलों की भयावहन जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन के लिए जंगलों की भयावहन जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है। ऐसे किसी के लिए जंगलों की भयावहन जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी जांबिया की व्यापक खाद्य संसाधन का अनुपात देता है।

निषेध संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं पर

